बी. सी. शिवशंकर

बनाम

बी. आर. नागराज

27 फरवरी, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और तरुण चटर्जी, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

उच्च न्यायालय द्वारा कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न की विरचना किए बिना 100-दूसरी अपील की अनुमति दी गई, जो उचित नहीं है।

एस.100 (5) की प्रयोज्यताः यह केवल तभी लागू होता है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ही विरचित किया जा चुका हो और यह उच्च न्यायालय को दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, "कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर" अपील सुनने का अधिकार देता है।

शब्द और वाक्यांश-"कानून के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का"-का अर्थ।

वर्तमान अपील में चुनौती प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर दूसरी अपील को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को दी गई है।यह तर्क

दिया गया कि दूसरी अपील को धारा 100, सी. पी. सी. के तहत आवश्यक कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न की विरचना किए बिना अनुमति दी गई थी।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विराचित किया गया है या इस प्रकार विरचना किए गए प्रश्न, यदि कोई हो, पर दूसरी अपील की सुनवाई की गई थी। ऐसा होने पर, निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।[पैरा 4]

1.2 धारा 100, सी. पी. सी. की उप-धारा (5) केवल तभी लागू होती है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ही विराचित किया जा चुका हो और यह जी उच्च न्यायालय को दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील सुनने का अधिकार देता है। "कानून के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पहले से ही तैयार किए गए कानून का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए और फिर केवल कानून का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए जो पहले विराचित नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए लिया जा सकता है, यदि इसका विचार है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।[पैरा 10]

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, [2000] 1 एस. सी. सी. 434; रूप सिंह बनाम राम सिंह, [2000] 3 एस. सी. सी. 708; कन्हैयालाल बनाम अनुपकुमार, [2003] 1 एस. सी. सी. 430; चडत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य, [2004] 6 एस. सी. सी. 359; जोसेफ सेवरेन बी और अन्य। वी.बेनी मैथ्यू और ओआरएस., [2005] 7 एससीसी 667; ससिकुमार और ओआरएस. वी.कुन्नथ चेलप्पन नायर और अन्य, [2005] 12 एस. सी. सी. 588 और ज्ञान दास बनाम ग्राम पंचायत, ग्राम सुन्नर कलान और अन्य, [2006] 6 एस. सी. सी. 271 पर भरोसा किया।

2. इन परिस्थितियों में विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। जहाँ तक यह कानून के अनुसार निपटारे के लिए दूसरी अपील से संबंधित है, मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।[पैरा 11]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय

2000 की सिविल अपील सं. 5452

आर. एस. ए. सं. 236/1991 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय डी के अंतिम निर्णय और डिक्री दिनांक 27.5.1998 से।

अपीलार्थी के लिए एस. एन. भट्ट।

न्यायालय का निर्णय इनमें द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. -

1. इस अपील में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के लिए है जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर दूसरी अपील को अनुमति देता है। मूल रूप से, तीन प्रतिवादी थे और वर्तमान अपील केवल प्रतिवादी नं. 1अन्य प्रतिवादियों को वर्तमान अपील में प्रतिवादी 2 और 3 के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन अपीलार्थी के अनुरोध पर उनके नाम एफ को हटा दिया गया था।हालाँकि अपील के समर्थन में कई बिंदुओं का आग्रह किया गया था, लेकिन हम समझते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 100 के तहत आवश्यक कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी।

2. नोटिस देने के बावजूद कोई भी प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुआ।

3.संहिता की धारा 100 "दूसरी अपील" से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार हैः

> "100 (1) इस संहिता के मुख्य भाग में या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, एक अपील उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री से उच्च न्यायालय को झूठ बोलना, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

(2) इस धारा के तहत एकतरफा पारित अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।

(3) इस धारा के तहत एक अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।

(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात, उसके द्वारा प्रणीत नहीं किए गए कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने के लिए नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।"

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विराचित किया गया है

या इस प्रकार विंराचना किए गए प्रश्न, यदि कोई हो, पर दूसरी अपील की सुनवाई की गई थी।कि ई ऐसा होने के कारण, निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

5. ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, [2000] 1 एस. सी. सी. 434 में इस न्यायालय ने पैरा 10 में इस प्रकार कहा हैः

> "10. अब धारा 100 सी. पी. सी. के तहत, 1976 के संशोधन के बाद, उच्च न्यायालय के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न विरांचित करना आवश्यक है और ऐसा किए बिना पहली अपीलीय अदालत के फैसले को पलटने की अनुमति नहीं है।"

6. रूप सिंह बनाम राम सिंह, [2000] 3 एस. सी. सी. 708 में इस न्यायालय ने व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अपील जी तक सीमित है जिसमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। उक्त निर्णय के पैरा 7 में कहा गया हैः

> "7. यह दोहराया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय की धारा 100 सी. पी. सी. के अधिकार क्षेत्र के तहत दूसरी अपील पर विचार करना केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और यह उच्च न्यायालय को विशुद्ध सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अधिकार

क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय तथ्य के प्रश्न। इसके अलावा, मामले का निपटारा करते समय, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील स्वीकार करते समय उसके द्वारा तैयार किए गए कानून के प्रश्न पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि विवादित फैसले में इसका कोई संदर्भ नहीं है।इसके अलावा, साक्ष्य की सराहना करने के बाद तथ्य खोजने वाली अदालतों ने कहा कि प्रतिवादी ने एक बटाई के रूप में परिसर के कब्जे में प्रवेश किया, अर्थात, एक किरायेदार के रूप में और उसका कब्जा अनुमत था और इस बारे में कोई अभिवचन या सबूत नहीं था कि यह कब प्रतिकूल और शत्रुतापूर्ण हो गया।नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए ये निष्कर्ष साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित थे और उन निष्कर्षों में कोई विकृति, अवैधता या अनियमितता नहीं थी। यदि प्रतिवादी को पट्टेदार के रूप में या बटाई समझौते के तहत वाद भूमि का कब्जा मिला है, तो अनुमेय कब्जे से उसे शत्रुतापूर्ण शत्रुता और वास्तविक मालिक के ज्ञान के प्रतिकूल कब्जे को दिखाने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित करना है।

लंबे समय तक केवल कब्जे के परिणामस्वरूप अनुमेय कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में परिवर्तित नहीं किया जाता है ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार, [1994] 6 एस. सी. सी. 591।इसलिए उच्च न्यायालय को नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

7. कन्हैयालाल बनाम अनुपकुमार, [2003] 1 एस. सी. सी. 430 में इस स्थिति को दोहराया गया है।

8. चडत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य, [2004] 6 एस. सी. सी. 359 में, यह इस प्रकार देखा गया थाः

"6. संहिता की धारा 100 को ध्यान में रखते हुए अपील के ज्ञापन में धारा 100 की उप-धारा (3) के तहत आवश्यक पर्याप्त प्रश्न या अपील में शामिल प्रश्नों का सटीक उल्लेख किया जाएगा।जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को उप-धारा (4) के तहत तैयार करेगा और दूसरी अपील की सुनवाई धारा 100 की उप-धारा (5) में बताए गए प्रश्न पर की जाएगी।"

9. इस न्यायालय द्वारा जोसेफ सेवरन और ओआरएस. वी. में स्थिति पर प्रकाश डाला गया था।बेनी मैथ्यू और ओआरएस., [2005] 7 एससीसी 667, ससिकुमार और ओआरएस. बनाम।कुन्नथ चेलप्पन नायर और अन्य, [2005] 12 एस. सी. सी. 588] और ज्ञान दास बनाम ग्राम पंचायत, ग्राम सुन्नर कलान और अन्य, [2006] 6 एस. सी. सी. 271।

10. धारा 100 की उप-धारा (5) केवल तभी लागू होती है जब कोई सारवान कानून का प्रश्न पहले ही तैयार किया जा चुका है और यह उच्च न्यायालय ए को दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कानून के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील सुनने का अधिकार देता है।"कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पहले से ही तैयार किए गए कानून का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए और फिर केवल कानून का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले तैयार नहीं किया गया था, उसे उच्च न्यायालय द्वारा बी दर्ज किए जाने के कारणों के लिए लिया जा सकता है, यदि इसका विचार है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।

11. इन परिस्थितियों में विवादित निर्णय को दरकिनार किया जाता है।जहाँ तक यह 1991 की दूसरी अपील संख्या 236 से संबंधित है, हम इस मामले को कानून के अनुसार निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हैं। अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

बी. बी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।